प्रेस विज्ञप्ति

संभावित कोल क्राइसिस से निपटने हेतु विद्युत उत्पादन निगम निरन्तर प्रयासरत

राज्य सरकार के 2170 मेगावाट क्षमता की तापीय इकाइयों हेतु ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने में सहमति

जयपुर, 29 मार्च 2022

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित केप्टिव कोल ब्लॉक से खनन प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु आवश्यक स्वीकृतियों के मिलने में लगने वाले समय के मद्देनजर कोल आधारित 4340 मेगावाट क्षमता की इकाइयों हेतु कोयले की समुचित व्यवस्था करने के लिए डा. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग और आर के शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्पादन निगम, राजस्थान ने कोयला मंत्रालय एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से ब्रिज लिंकेज के माध्यम से आवंटन हेतु कोयला आवंटित करने का निवेदन किया।

इस हेतु माननीय मुख्यामंत्री राजस्थान सरकार ने भी संभावित कोयले के संकट को ध्यान में रख एवं राज्य के बिजलीघरों में कोयले की सुचारु व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोयला एवं खान मंत्री, कोयला मंत्रालय भारत सरकार से आग्रह किया था। संभावित कोल क्राइसिस के मद्देनजर ऊर्जा मन्त्री, राजस्थान सरकार श्री भंवर सिंह भाटी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग डा. सुबोध अग्रवाल ने मार्च माह में ही दिल्ली जाकर ऊर्जा एवं कोल मंत्रालय, भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से मुलाकात कर अतिशीघ्र ब्रिज लिंकेज हेतु आग्रह किया था।

राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम के निवेदन पर कोयले की व्यवस्था हेतु स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी को उक्त समय के दौरान कोयले की व्यवस्था करने के लिए सिफारिश की।

आज दिनांक 29 मार्च 2022 को दिल्ली में श्री वीके तिवारी अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई जिसमें ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, सीईए एवं कोल् इंडिया के प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में विद्युत उत्पादन निगम से श्री आर के शर्मा सीएमडी एवं श्री देवेंद्र श्रृंगी अतिरिक्त मुख्य अभियंता फ्यूल ने उपस्थित होकर राजस्थान में कोयले आधारित 4340 मेगावाट क्षमता की विद्युत् तापीय इकाइयों के लिए कोयले की आवश्यकता हेतु अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखा तथा 2170 मेगावाट क्षमता की इकाइयों हेतु 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने की औपचारिक सहमति प्राप्त करने में सफलता हासिल की ।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के इस निर्णय से उत्पादन निगम को लगभग 6 से 7 रेक प्रतिदिन कोयले की आपूर्ति होने की सम्भावना है।